

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए.मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No.P-2/72/2024 Shri Kuldeep Dubey Owner, Near Shubham lodge, Subhash Coloni, Guna, Guna, Madhya Pradesh-473001, Prior Environment Clearance for Flag Stone - 6000 M3/Year, Lease Area- 1.65 ha., at kh No. 947/1,948, VILL.- JAKHAUDA, TEH - GHATIGAON,,Distt. Gwalior (M.P.), (MIN/449980/2023)**
(TOR)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kuldeep Dubey, Owner,online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारी मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.)उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Kuldeep Dubey Owner, Near Shubham lodge, Subhash Coloni, Guna, Guna, Madhya Pradesh-473001, Prior Environment Clearance for Flag Stone - 6000 M3/Year, Lease Area- 1.65 ha., at khasra No. 947/1,948 , VILLAGE - JAKHAUDA, TEHSIL - GHATIGAON,,Distt. Gwalior (M.P.), [SIA/MP/MIN/449980/2023].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 947/1,948 Part,	एरिया- 1.65 ha., शासकीय भूमि

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

परियोजना स्थल	VILLAGE - JAKHAUDA, TEHSIL - GHATIGAON, Distt. Gwalior
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 71023 दिनांक 18/08/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी-1.
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Non Blasting only Drilling. (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	Flag Stone - 6000 M3/Year,
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 12.570 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – जखौदा, जिला – ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 28 दिनांक 16/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing –No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में से एक पगडंडी निकल रही है जो कि आम रास्ता नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण –पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 22/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी।

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियो ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
6. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।
12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबैक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- 13- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
- 14- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूषप्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
15. खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

16. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
17- Surface run-off study shall be submitted with EIA.

2. Case No P2/309/2024 Lamta Pressurized Pipe Irrigation Network (Hose System) Project Executive Engineer, Water Resources Survey Division Balaghat. Prior Environment Clearance for Lamta Pressurized Pipe Irrigation Network (Hose System) Project (M.P.). Culturable Command Area (CCA) - 9,636 Ha., Non-Forest Land-0.4625 Ha., (Water lifting points are about 1.5 km and 3.5 km upstream of Dhuty Weir). [RIV/457642/2024] (B2).

This is a Micro Lift Irrigation Project, this project has a command area of 9,636 ha; therefore, as per EIA notification of September 2006 and subsequent amendment dated 14th August 2018, it is a Category B2 project (Medium irrigation project having CCA > 2000 ha and < 10000 ha)” and hence shall be appraised by SEIAA/SEAC, Madhya Pradesh.

Following details submitted by PP on Parivesh portal :

SN.	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/RIV/457642/2024.
2.	Project Name	Shri UDAY PARTE, Executive Engineer, Water Resources Survey Division Balaghat (M.P.) – 481001, Prior Environment Clearance for Lamta Pressurized Pipe Irrigation Network (Hose System) Project (M.P.). Culturable Command Area (CCA) - 9,636 Ha., Non-Forest Land-0.4625 Ha.,
3.	Project Proposal For	Fresh EC.
4.	CCA details	9,636 Ha. (B2 Cat)
5.	Land Use	Govt. Land.
6.	Project Cost Rs.	14650 Lakhs.
7.	River	The water will be sourced from the submergence area of Dhuty Weir on Wainganga River in Balaghat District.
8.	Description of Project.	The proposed Lamta Pressurized Pipe Irrigation Network (Hose System) Project is planned to irrigate a total of 9,636 ha of Culturable Command Area (CCA) spread over 56 villages of Balaghat Tehsil in Balaghat District. The water will be sourced from the submergence area of Dhuty Weir on Wainganga River in Balaghat District. The water lifting points are about 1.5 km and 3.5 km upstream of Dhuty Weir. The water will be lifted through Rising for Hose Irrigation to deliver at farmer’s field up to 5 ha chak field with a duty of 0.45 lit/sec/ha.
9.	Source of filling material	Muck excavated from laying of pipeline.

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

10.	Dam height from the deepest foundation level (m)	4.9
11.	Length of the Dam (m)	503.53
12.	Maximum Height of the Embankment	4.9
13.	Type of Irrigation	Drip Irrigation.
14.	CTE/CTO Status	Will be obtained after EC.
15.	DFO NOC	DFO office, Balaghat Letter No. 4228 dated 22/11/2023.
16.	PWD distance letter	EE, PWD, Divion -1, Distt.- Balaghat Letter No. 6013 dated 11/10/2023. Inter State Boundary distance -113 km (Chhattisgarh State). Inter State Boundary distance - 93 km (Maharashtra State).
17.	EMP/ Env. Con	R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd., Gurugram (Haryana)

The case was presented by the Shri Vimal Garg, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd., Gurugram (Haryana) along with PP Shri UDAY Parte, Executive Engineer, Water Resources Survey Division Balaghat.

PP submitted following information about the project:-

- The project is proposed by WRD, MP to provide irrigation water to Balaghat Tehsil in Balaghat District.
- The project will cater irrigation water to 9636 ha of CCA in 56 villages in Balaghat Tehsil of Balaghat District.
- The water will be sourced from the submergence area of Dhuty Weir on Wainganga River in Balaghat District.
- The water lifting points are about 1.5 km and 3.5 km upstream of Dhuty Weir.
- The proposed water lifting points are about 1.5 km and 3.5 km upstream of Dhuty Weir.
- Command area of 9,636 ha is spread in Balaghat tehsil of Balaghat district.
- The project comprises of main components namely intake structures at the left bank of Wainganga River, distribution chamber, rising mains and distribution network.
- Water is proposed to be lifted from Wainganga River, about 1.5 km and 3.5 km upstream of existing Dhuty Weir.
- The water will be lifted through Rising Main for Hose Irrigation to deliver at farmer's field up to 5 ha chak field with a duty of 0.45 lit/sec/ha.

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

- A total of 4.334 cumec of water will be lifted in this scheme during Kharif season only
- Command Area 2 = **4697 ha.**
- Length of Rising Main = **1.80 km.**
- Length of Gravity Main = **14.92 km**
- Length of distribution network = **92 km**

NO PERMANENT PRIVATE OR FOREST LAND REQUIRED FOR THE PROJECT

Permanent land requirement is 0.4625 ha:

State Revenue Dept.: 0.2825 ha

Ownership of WRD: 0.1800 ha

Temporary land requirement for laying pipeline is 9.71 ha:

Government Land: 1.70 ha

Private Land: 8.01 ha

LAND REQUIREMENT

S. No.	Project Component	Land Required (ha)	Ownership
Permanent Requirement			
1	Distribution Chamber	0.09	Revenue Dept.
2	Pump House - 1	0.09	WRD
3	Pump House - 2	0.09	WRD
4	Approach Road for Distribution Chamber	0.1925	Revenue Dept.
Sub Total		0.4625	
Temporary Requirement			
5	Underground Pipeline	8.01	Private
6	Underground Pipeline	1.7	Revenue Dept.
Sub Total		9.71	

Regarding Tree Felling :

- Area of 0.09 ha required for pump house 1 is a part of 0.367 ha land parcel of WRD, Balaghat located at village Budhiagaon, Khasra No. 1.
- Joint inspection by the officials of forest dept., revenue dept. and WRD was carried for tree enumeration.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

- During tree enumeration total 27 trees of various girth of Sagaun, Saja, Mahua, Palash, Arjun etc. were identified which are required to be felled.
- District Collector, Balaghat in his Order dated 16/02/2024 has granted permission to WRD to cut total 27 trees on this land parcel with conditions:
- Plantation of different tree species in the compound
- Trees will be cut under the direction of forest dept. and in presence of forest and revenue dept.
- Entire wood will be deposited in the yard of forest dept. for further necessary actions at their end.

प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति में परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

1. PP shall submit KML map, showing co-ordinates of the command area of project site.
2. Submit list of farmers who are affected by laying of pipelines passing through their fields.
3. The PP shall ensure power generation from non- conventional sources of energy i.e. **solar power** etc.
4. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources and through tree felling shall be submitted along with their management plan w.r.t. carbon foot print.
5. Top soil disposal management plan, which shall be generated during digging of land for laying of pipelines.
6. जल वितरण स्थानीय किसानो को किया जाना है अतः इस के वितरण कि नीति क्या रहेगी प्रस्तुत करें।
7. जल वितरण ग्रेविटी के अनुसार किया जाना है अतः इसकि तकनीकि रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
8. परियोजना की तकनीकि फिसिबिलीटी रिपोर्ट सक्षम प्राधीकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें।
9. Soil Swelling Factor की गणना 25% के आधार पर की गयी है अतः इस के रिफ्रेन्स प्रस्तुत करें।
10. Fertile and Non-fertile Soil की गणना का पृथक-पृथक प्रबंधन प्रस्तुत करें।
11. Muck Management Plan with financial implication in the EMP.
12. Submit proper area statement regarding Forest land/ Private land/ Revenue land etc.
13. Separate CAT plan as per legal status of land shall be approved by competent authority.
14. जिन किसानो को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा प्रदान करेगें उन किसानो को श्री-अन्न योजना एवं उन्नत कृषि की जानकारी का प्रस्ताव, क्राॅप डायवर्सिफिकेशन, पानी के बचत के उपाय, कृषि वानिकि, ट्री-एडप्टसन् स्कीम, कार्बन फुटप्रिन्ट आदि के लिये जन-जाग्रति कार्यक्रम के प्रस्ताव CER योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

3. **Case No P-2/74/2024 Shri Bhrighu Gupta, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra, U.P., Owner, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra, U.P. – 231222, Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a production capacity of Max 58544 m3/year Gitti having a lease area of 2.01 hectare, at Khasra No.-129/1,129/2,129/3,141/1/2,141/2, Village -Karami Tehsil- Mada, District- Singrauli (M.P.) (MIN/458953/2024) (TOR).**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Brighu Gupta online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Bhrighu Gupta, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra, U.P., Owner, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra, U.P. – 231222, Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a production capacity of Max 58544 m3/year Gitti having a lease area of 2.01 hectare, at Khasra No.-129/1,129/2,129/3,141/1/2,141/2, Village -Karami Tehsil- Mada, District- Singrauli (M.P.). [458953].	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 129/1,129/2,129/3,141/1/2,141/2,	एरिया— 2.01 ha., निजी भूमि
परियोजना स्थल	Village -Karami Tehsil- Mada, District- Singrauli (M.P.).	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 13321 दिनांक 05/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Blasting, Drilling, Crushing . (As per Parivesh Portal up-loaded information). 	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	Stone - 58544 M ³ /Year,	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4214 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 19.92 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4214 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

	परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4214 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। • मरघट -300 मी. दूरी।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत -करामी, जिला - सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र०. निरंक दिनांक 02/10/2022 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 225 दिनांक 16/01/2025 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम सम्पूर्ण प्रक्रिया संपादन उपरांत जोडा जावेगा।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ / झाड़ियाँ लगे दिख रहे हैं, अतः इनका अध्ययन विषय विशेषज्ञ से कराकर, उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. Ecological services assessment (wrt tree felling) and management plan shall be submitted with the EIA report.
4. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
7. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

9. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
13. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबैक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- 14- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 15- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ ो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

4. Case No P-2/73/2024 Shri DEVENDRA LODHI, OWNER (PROJECT PROPONENT), Village Sillarpur, Post Gourjahamar, Tehsil Deori District Sagar (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (25,000 cum per annum) (Khasra No. 26/1) Village - Ramanna, Tehsil - Deori, District Sagar (M.P.) (MIN/458343/2024) (TOR)

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लारिस्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

5. Case No 10662/2024 SHRI NARENDER GOYAL, Owner of Chemigreen Chemical 156, Ravi Nagar, Behind GDA Office, Gwalior(M.P.), 474009. Prior Environment Clearance for Proposed Synthetic Organic Chemical Production (Azodicarbonamide -Adc, Dinitroso Pentamethelene Tetramine- DNPT) By Chemigreen Chemicals. At Plot No. 19, 20 GAA Industrial Area, Malanpur, Dist.-Bhind(M.P.), Product & Production Capacity - Azodicarbonamide-ADC, Dinitrosopentamethelene

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

Tetramine (DNPT) Capacity - 3000 TPA, Total Plot Area of 8000 M2 (IND3/459571/2024) (EIA).

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed project for Manufacturing of Synthetic Organic Chemicals (Azodicarbonamide -ADC, Dinitroso Pentamethelene Tetramine- DNPT) at Plot No. 19,20 in Malanpur Industrial area Dist Bhind M.P.[Cat. 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry Project.

In the 696th SEAC Meeting Dated 22/11/2023 the ToR was recommended by the Committee.

PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line on Parivesh Portal. Which was accepted by SEAC hence and the same was scheduled in the agenda.

The PP submitted following details on Parivesh portal are as .

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/IND3/459571/2024.
2.	Project Name	SHRI NARENDER GOYAL, Owner of Chemigreen Chemical 156, Ravi Nagar, Behind GDA Office, Gwalior(M.P.), 474009. <i>Prior Environment Clearance for PROPOSED SYNTHETIC ORGANIC CHEMICAL PRODUCTION (AZODICARBONAMIDE -ADC, DINITROSO PENTAMETHELENE TETRAMINE- DNPT) By ChemiGreen Chemicals. At Plot No. 19, 20 GAA Industrial Area, Malanpur, Dist.-Bhind(M.P.), Product & Production Capacity- Azodicarbonamide - ADC, Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT) Capacity - 3000 TPA, Total Plot Area of 8000 M², <u>Cat: 5(f) Synthetic organic chemicals industry.</u></i>
3.	Description of Project	M/s Chemicgreen chemicals proposes to set up a new project to produce synthetic organic chemical namely Azodicarbonamide -ADC, Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT) at Plot No. 19/20 Industrial Area, Malanpur, Dist-Bhind (MP) with production capacity of 3000 TPA. The proposed activity is permitted as per main object clause of Memorandum of Association of the company. These products are manufactured in campaigns through multi-step organic synthesis using batch processes. The product portfolio is a mix of high volume, low value and low volume, high value products. The site has modern state-of-the-art plants facilitating minimal manual intervention and consistent reproduction of processes, on an ongoing basis, and these are built to GMP standards. The cost of proposed is Rs. 4.12 Crores.
4.	Project Cost (Rs)	4.12 Crores.
5.	EC Status	New. (Fresh EC).
6.	ToR Status	ToR Recommended in 696 th SEAC Meeting Dated 22/11/2023. ToR Valid up to 21/11/2027.

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

7.	Project Location	Plot No. 19/20 Industrial Area, Malanpur, Dist-Bhind (MP)
8.	Plot Area details	Total Plot Area of 8000 M ²
9.	ToR Proposed	Submitted by PP.
10.	Land Allotment Deed date	22/06/2023.
11.	latitude longitude details	latitude 26°346165'N and longitude 78°270883
12.	Water NoC	EE, MIDC, Gwalior NoC dated 08/09/2023.
13.	DG set capacity	1 DG Set of 65 KVA.
14.	PFR	Submit.
15.	Environmental Consultant	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) Valid up to March 22, 2026.

The case EIA presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) and PP Mr. Mohit Chauhan, General Manager. PP submitted that the proposed unit will be designed to specialize in manufacturing of Synthetic Organic Chemicals (Azodicarbonamide -ADC, Dinitroso Pentamethelene Tetramine- DNPT)with proposed capacity of the project is of 3000 TPA. These products will be used in rubber industry.

The salient features of the projects are :

- The project occupies Total Plot Area of 8000 M², is proposing production of APIs. The total fixed cost of the project is INR 4.12 crore Lakhs as per the company gross book value.
- The major facilities involved area Boiler, MEE, Effluent Treatment Plant (ETP), and R.O Plant Facilities like administrative office, parking and greenbelt/plantation also developed as per plan/requirement.

Project Name	Manufacturing of Azodicarbonamide -ADC, Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT)
Location	Malanpur Industrial area Dist. Bhind (MP)
Production capacity	3000 MT per Anum
Estimated Project Cost	Proposed : 4.12 Crore
EMP Cost (Capital)	Proposed : 64.50 Lacs
EMP Cost Recurring	Proposed : 36.40 Lacs
Acquired Land	8000sqmtrs
Total Water Consumption	33.60 KLD
Net fresh Water Consumption	As fresh water 17.60 KLD as 16KLD of treated water will be recycled.
Source of Water Supply	AKVN
Waste Water Generation	22.55 KLD

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

Treatment Facility proposed	Effluent treatment facility ETP is of 25 KLD, RO of 20 KLD and proposed MEE of KL/day. The treated water will be used for recycling, cooling towers, floor washing and green belt.
Source of power supply	Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Co Ltd., Bhopal
Power Requirement	Total :125 KVA
Fuel Options Coal/Agro waste (TPD) FO (Lit/Hr)	Total : For steam Boiler (2TPH) PNG kg /hr For DG set (-65-KVA) HSD -10 Lit/hour
Major Equipments	Reactors, Tanks, Pulveriser, blower Boiler (2 TPH), Cooling Tower, MEE, ETP, Dryer Centrifuge , DM Water and RO etc.
Green belt (sqmt)	2640 Sq Meter
Employment generation	40 to 45 no.
CER Cost	5.0 Lacs

PP further submitted that the effluent treatment scheme including segregation of effluent streams for units adopting 'Zero' liquid discharge will be implemented, for better housekeeping by regular steaming of all equipment's shall be done to avoid odour generation. Efficient biocides shall be utilized to control bacterial contamination. Control of temperature Regular use of bleaching powder in the drains shall be done to avoid generation of putrefying micro-organisms. Closed operation of the process shall be practiced effectively.

The wastewater will be sent to ETP, RO and MEE. Hence, the industry will remain **zero discharge** all the time. Effluent treatment facility ETP is of 25 KLD, RO of 20 KLD and proposed MEE of 4 KL/day. The treated water will be used for recycling, cooling towers, floor washing and green belt.

In the project, total 33% (2640 sqm.) of the total area is proposed as green belt, which is developed as greenbelt development. PP further submitted that for solar power unit of 40 kVA and PNG based Boiler of 2 TPH is proposed to meet the out the reduction in carbon foot print. The Unit is proposed carbon sequestration of 26,40,000 kg during project life.

After deliberations and the submissions made by the PP, were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of **Prior Environment Clearance to M/s. Chemi Green Chemicals for Manufacturing of Azodicarbonamide -ADC, Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT) at Plot No. 19,20 GAA in Malanpur Industrial area Dist Bhind M.P.[M.P.[Production**

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

Capacity - 3000 Tonnes per Annum of Azodicarbonamide -ADC, Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT).

List of proposed EC product details are as given below:

S.No.	Name Of Proposed Product	Quantity in TPA	Major Uses/ End Use
1	Azodicarbonamide -ADC,	1800+1200	Shoe/ Rubber Industries
2	Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT)		
Total (TPA)		3000	

Subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act 1986.
2. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (if applicable). The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

3. Storage of raw materials, coal etc. shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
4. The DG set (1X65 KVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
5. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608 (E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
6. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
2. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
3. The Waste water will be treated though ETP is of 25 KLD, RO of 20 KLD and proposed MEE of 4 KL/day. The MEE condensates will be send to ETP for further treatment and shall be recycled / reutilized back in plant utility .MEE bottom will be sent to TSDF site
4. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
5. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
6. Total water requirement of 33.60 kld and fresh water requirement shall not exceed 17.60 KLD.
7. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
8. The Company shall harvest rain water from the roof tops of the buildings and

storm water drains to recharge the groundwater and utilize the same for different industrial operations within the plant.

9. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG (1X65 KVA) set for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The total power requirements for project will be 125 KVA The power will be supplied by MPPK Vidyut Vitaran Company Limited Malanpur Region.

(F) Waste management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous wastes such as organic incinerable wastes/residues, used filter bags, packaging materials, rejected/expired raw materials and off specification/ rejected finished products from the manufacturing plants shall be directly sent to TSDF, Pithampur/ Recyclers / Pre or coprocessors
3. The Fly ash generated from boilers shall be stored in Covered shed and disposed of through cement manufacturers or brick manufacturers by bulkers / closed containers and should comply with Fly Ash Utilization Notification, 1999 and as amended subsequently.
4. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
5. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

6. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
7. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is atleast 150mm above the maximum flood level.
8. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
9. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
10. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
11. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
12. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
13. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
14. ETP sludge, process inorganic & evaporation salt shall be disposed off to the TSDF/ Preprocessor.
15. The company shall undertake waste minimization measures as below:
 - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - c. Use of automated filling to minimize spillage.
 - d. Use of Close Feed system into batch reactors.
 - e. Venting equipment through vapour recovery system.
 - f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce waste water generation.

(G) Green Belt

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

1. Total 1000 trees shall be planted in the area of 2640 sq. mtrs (33 % of total plot area) which is developed as greenbelt development.
2. Plantation details are as given below:-

Description	Qty.	Location
Putran Jeeva	50	Boundary Wall /Along the road
Ficus Viral	100	Road Main Gate - Admin Block
Satparni	100	Around Admin Block, road & lawn
Ashoka Tree	100	Around Admin Block, road & lawn
Mehandi	300	Around Admin Block, lawn and around boundary limit (backside of the site)
Kanak Champa	250	Along the Boundary Wall /
Rat Rani	100	Along internal road
TOTAL	1000	200 number of trees shall be around the periphery/road side at outside of the unit

3. The additional green belt of 5-10 m width along road sides 200 No . Selection of plant species shall be as per the CPCB guidelines in consultation with the State Forest Department.
4. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2.5 feet height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature and species as suggested by the committee. As proposed 1000 nos. of plants shall be planted green belt mainly along the periphery of plot PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

- the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
 4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
 5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
 6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
 7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP & Corporate Environment Responsibility

1. The proposed EMP capital cost is Rs. 64.50 lakhs and 36.40 lakhs/year as recurring cost .
2. Under CER activity, capital cost is Rs. 5.0 lakhs proposed for following different activities.

Commitment For CER Activities		
SN	Proposed Activity	Cost in RS
1	One warmer machine, Two AC (2tonne), 4 complete bed at primary Health center Malanpur Dist Bhind (MP)	Rs 5.0 Lacs
Total		Rs 5.0 Lacs

3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/ violation of the environmental/forest/ wildlife norms/

conditions. The company shall have defined system of reporting infringements deviation/violationoftheenvironmental/forest/wildlifennorms/conditionsandorshareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

4. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
5. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
6. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

(J) Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC &SEIAA.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing (if applicable) and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of law relating to the subject

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. **Case No P-2/76/2024 Shri JULPHAKAR KHAN, R/o-Village- Lohari, Tehsil-Kasrawad, District-Khargone, M.P. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.50 ha. (Murrum – 7000 Cubic meter per year) (Khasra No. 196), Village - Gujari, Tehsil- Kasrawad, District- Khargone (M.P.). (MIN/459628/2024) (B2)**

प्रस्तावित Murrum खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Julphakar Khan online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri JULPHAKAR KHAN, R/o-Village- Lohari, Tehsil-Kasrawad, District-Khargone, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	196 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.50 hectare.
स्थल	Village - Gujari, Tehsil- Kasrawad, District- Khargone (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1719 दिनांक 11/12/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum – 7000 Cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Murrum – 7000 Cubic meter per year है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1927 दिनांक 19/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1927 दिनांक 19/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं	

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1927 दिनांक 19/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 150 मीटर पर तालाब स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लोहरी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 16/8/23. अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - 12 Tree Felling - 06 परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि 300 अतिरिक्त लगाये जायेंगे ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- नहर लगभग 130 मी. एवं कच्चा रोड 160 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1928 दिनांक 19/01/24 उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला आगरमालवा में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरम-7000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.60 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम गुजारी शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में विद्यालय विकास हेतु राशि भूप्रवेश प्राप्त मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी ।	80,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------------	---------------------	---------------------

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

1	बैरियर जोन में	कालासिरिस, खमेरसफेदसिरिस, नीम, कस्टार, सिस्सू, चिरोल, करंज, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	700 पौधे
2	परिवहन मार्ग में	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	100 पौधे
3	ग्राम गुजारी के शासकीय विद्यालय परिसर में	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	100 पौधे
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200 पौधे

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No P-2/77/2024 Shri SANJAY MEHTA, R/o-25, Namak Mandi, Ujjain, Dist. Ujjain (M.P.). M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti), Murrum and M-Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone (Gitti) – 30000 Cum/Annum, Murrum - 30000 Cum/Annum and M-Sand – 45000 Cum/Annum) (Khasra No. 38), Village - Bodani, Tehsil- & District- Ujjain (M.P.). (MIN/444148/2023)**

प्रस्तावित Murrum खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sanjay Mehta online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SANJAY MEHTA, R/o-25, Namak Mandi, Ujjain, Dist. Ujjain (M.P.)

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	38 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.0 hectare.
स्थल	Village - Bodani, Tehsil- & District- Ujjain (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 686 दिनांक 19/6/20 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	सिया के पत्र क्रमांक 6296 दिनांक 12/2/21 के द्वारा मुरूम – 8000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) – 30000 Cum/Annum, Murrum - 30000 Cum/Annum and M-Sand – 45000 Cum/Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitti) – 30000 Cum/Annum, Murrum - 30000 Cum/Annum and M-Sand – 45000 Cum/Annum है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 05/7/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 05/7/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 05/7/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बॉसखेड़ी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 08/3/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - No	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लीज क्षेत्र के अन्दर उनका साईट ऑफिस स्थित है।	

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

	उत्तर दिशा—
	दक्षिण पूर्व दिशा— आबादी 400 मी. एवं पक्की रोड लगभग 440 मी.
	पूर्व दिशा—
	पश्चिम दिशा— वेयर हाउस लगभग 63 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया की 35 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 05/7/23 उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला आगरमालवा में सम्मिलित कर ली जावेगी।

पश्चिम दिशा में एक वेयर हाउस लगभग 63 मी. की दूरी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया की 35 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है, अतः खनन योग्य क्षेत्र लगभग 3.16 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone (Gitti) – 30000 Cum/Annum, Murrum - 30000 Cum/Annum and M-Sand – 45000 Cum/Annum है
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 35.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.43 लाख प्रति वर्ष ।
3. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बोड़ानी के श्री श्याम गौशाला में अधोसंरचना विकास हेतु गौशाला संग को वित्तीय सहायता दी जाएगी।	2,00,000

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (880 मीटर) पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा	सीताफल, काला सिरस, सफेद सिरस, अंजन, कुसुम, नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिरसु आदि।	700
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1000 मी) के दोनों ओर 4 फीट की ऊँचाई वाले पौधे लगाये जाएंगे ट्री गार्ड के साथ में।	काला सिरस, सफेद सिरस, अंजन, कुसुम, नीम, पीपल, करंज, चिरोल आदि।	1000
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण।	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल आदि।	2800
4	ग्राम बोड़ानी के श्री श्याम गौशाला में पौधा रोपण किया जायेगा। 4 फीट की ऊँचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में।	काला सिरस, सफेद सिरस, अंजन, कुसुम, नीम, पीपल, करंज, चिरोल आदि।	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. **Case No P-2/78/2024 Shri SANTOSH TUMRAM, Lease Owner, Balarpur, Gram - Balarpur, Sihora, Seoni (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 10) Village - Radhadehi Tehsil- Seoni, District - Seoni (MP) (MIN/454044/2023) (TOR).**

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Santosh Tumram online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SANTOSH TUMRAM, Lease Owner, Balarpur, Gram - Balarpur, Sihora, Seoni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	10 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	2.00 hectare.
स्थल	Village - Radhadehi Tehsil- Seoni, District - Seoni (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 450 दिनांक 14/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 721 दिनांक 04/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.60 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 721 दिनांक 04/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 721 दिनांक 04/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिठली जिला सिवनी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य पंचायत ने सशर्त कोई आपत्ति	

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

	नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing -05 Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— हॉलेज रोड लगभग 378 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 721 दिनांक 04/12/23 अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियो ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ।
6. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

- स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
 9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
 11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
 12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबैक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
 - 13- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
 - 14- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ ो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
 - 15- Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map is to be discussed in the EIA report.

9. Case No P2/310/2024 KALYANTOLL INFRASTRUCTURE LIMITED R/o-47 Somani Nagar Arodram road Indore,M.P. It is a Stone Quarry with a production capacity of Gitti – 80000 Cubic meter per year and M-Sand – 20000 Cubic meter per year having a lease area of 3.93 hectare, at Khasra No. 1545/2 & 1545/4, Village - Bargaon Buzurg, Tehsil- Pandhana, District- Khandwa (M.P.) [MIN/459905/2024] (B2). T.P.

प्रस्तावित Stone खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक अमित गुप्ता, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Amit Gupta. KALYAN TOLL INFRASTRUCTURE LIMITED, Authorized Person R/o-47 Somani Nagar Aro dram road Indore, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1545/2 & 1545/4 (निजी भूमि)	3.93 hectare.

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

स्थल	Village - Borgaon Buzurg, Tehsil- Pandhana, District- Khandwa (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 22/12/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 80000 Cubic meter per year and M-Sand – 20000 Cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti – 80000 Cubic meter per year and M-Sand – 20000 Cubic meter per year है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 25/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 25/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 25/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग जिला खंडवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 16/8/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज एरिया के बीच में से एक नाला निकल रहा है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया नाले के दोनो ओर 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है । उत्तर पश्चिम दिशा- आबादी लगभग 305 मी. दक्षिण पूर्व दिशा- निर्माणाधीन वेयर हॉउस लगभग 125 मी. पूर्व दिशा- आबादी लगभग 342 मी.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला खंडवा में सम्मिलित कर ली जावेगी।
----------------------------------	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान को अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित है। लीज एरिया के बीच में से एक नाला निकल रहा है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया की 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है, अतः खानन् योग्य क्षेत्र लगभग 1.72 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। दक्षिण पूर्व दिशा में एक वेयर हॉउस लगभग निर्माणाधीन है के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने ग्राम पंचायत का पत्र क्र.- 17 दिनांक 20/02/24 प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Gitti - 80000 Cubic meter per year and M-Sand - 20000 Cubic meter per year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.17 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जावे।

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु. में
ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशि भूप्रवेश के 03 माह के अंदर प्रदान की जावेगी।	80,000/-
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोरगांव बुजुर्ग में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 03 माह के भीतर जमा की जावेगी।	80,000/-
Total	160,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4780 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-आवलों, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	850 पौधे
2	गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-आवलों, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500 पौधे
3	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 300 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादि।	100 पौधे
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुंगना, कटहल आदि।	3280 पौधे
5	ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50 पौधे

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. **Case No P-2/80/2024 Shri Pawan Kumar Mittal, Partner, M/s SHARDA MINERALS, 26, Commercial Complex, Housing Board Colony, District Katni, (M.P.). Prior Environment Clearance for dolomite Mine in an area of 1.870 ha. (15,015 cum per annum) (Khasra No. 340) Village Malhan, Tehsil Badwara District Katni (M.P.). (MIN/457584/2024) (TOR)**

प्रकरण आज सेक की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

11. **Case No P-2/81/2024 Shri Vijay Kumar Mittal, Partner, M/s MAA NARMADA STONE ENTERPRISES, 26, Commercial Complex, Housing Board Colony, District Katni (M.P.). Prior Environment Clearance for dolomite Mine in an area of 2.90 ha. (50]661 cum per annum) (Khasra No. 225/2, 226/1, 226/2 & 309) Village Malhan, Tehsil Badwara District Katni (M.P.). (MIN/457527/2024) (TOR)**

प्रकरण आज सेक की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

12. **Case No P-2/79/2024 Shri Kishore Kumar Khare, Partner, M/s KHARE STONE AND TILES, Khirhani Phatak, District Katni (M.P.). Prior Environment Clearance for Flage Stone Mine in an area of 2.85 ha. (2]349 cum per annum) (Khasra No. 1259) Village- Dang, Tehsil- Rithi, Dist- Katni (M.P.). (MIN/457996/2024) (TOR)**

प्रस्तावित Flage Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kishore Kumar Khare, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स Ambiental Global Private Limited, Ghaziabad (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Kishore Kumar Khare, Partner, M/s KHARE STONE AND TILES, Khirhani Phatak, District Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1259(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.85 hectare.
स्थल	Village- Dang, Tehsil- Rithi, Dist- Katni, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 5231-33 दिनांक 01/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन-2,349 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन-2,349 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2844 दिनांक 22/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 05.98 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2844 दिनांक 22/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2844 दिनांक 22/12/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्रामीण कच्चा रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डांग जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-34 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने ईआईए रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने कथन दिया है ।	

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियो ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ।
6. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- 13- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 14- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

13. Case No P-2/82/2024 Shri RAVI SHIVHARE, LEESSEE, Ward no 06, barigarh chhatarpur (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 1222/2 (Govt) [1222/1, 1239/2/KHA, 1239/4/2, 1240/3, 1251) Village - Mudahara, Tehsil- Gaurihar, District- Chhatarpur (M.P.) (MIN/457735/2024) (B2).

B

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri RAVI SHIVHARE, online एवं उनके

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAVI SHIVHARE, LEESSEE, Ward no 06, barigarh chhatarpur jujhar nagar Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1222/2 (Govt) [1222/1, 1239/2/KHA, 1239/4/2, 1240/3, 1251 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village - Mudahara, Tehsil- Gaurihar, District- Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 12781-82 दिनांक 25/09/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2898 दिनांक 26/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.211 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2898 दिनांक 26/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2898 दिनांक 26/10/23 अनुसार 6 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रतोली (उ.प्र.) स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुडहरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 26/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing -05 Tree Felling - 05 Additional tree to be planted - 50	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 3148 दिनांक 21/12/23 अनुसार उक्त खदान अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित	

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

	<p>किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया की लीज क्षेत्र दो भाग में है जिसमें से दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र में छोड़ा गया है एवं इसी भाग में पौधा रोपण किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—10,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 13.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुये है अतः 25 मी. का सेड बैंक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

9. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल मुड़हरा में लकड़ी के फर्नीचर (बीस नग बेंच एवं डेस्क)	60,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1250 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, जंगल जलेबी, करंज, सिस्सू, चिरोल, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	नॉन माइनिंग जोन	आम, संतरा नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. **Case No P-2/83/2024 Shri AMIT KANOONGO, R/o- 11-Prayag Park Colony, Sanawad, Khargone, Madhya Pradesh- 451111. Prior Environment Clearance for Stone and M-sand Quarry in an area of 3.601 ha. (Stone 25,000cum/year and M-sand-**

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

30,000cum/year) (Khasra No. 84/1,84/3,84/4,84/5,84/6 & 84/7), village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (M.P.) (MIN/458268/2024 (TOR)

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Amit Kanoongo, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Aseries Envirotek India Private Limited उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Amit Kanoongo, R/o- 11-Prayag Park Colony, Sanawad, Khargone, Madhya Pradesh- 451111
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	84/1,84/3,84/4,84/5,84/6 & 84/7 3.601 hectare. (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1374 दिनांक 06/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone 25,000cum/year and M-sand-30,000cum/year घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone 25,000cum/year and M-sand-30,000cum/year -घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 12/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 12/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 12/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

	तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिगड़ी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 23 दिनांक 14/4/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1858 दिनांक 08/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियो ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ।
6. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबैक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- 13- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 14- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

15. Case No 8924/2022 Shri Maya Dixit, Owner, Maya Dixit D/o Shri Ramswaroop Dwivedi R/o Subhash Bazaar Hameerpur (U.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (50]000 cum per annum) (Khasra No133 (P) Village- Saila, Tehsil Maharajpur, Distt. Chhatarpur (M.P.) (MIN/457062/2023) (EIA)

प्रकरण आज सेक की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

16. Case No P-2/93/2024 Mr. KRISHNA PAL SARAN, Director, 151, SARAN SADAN, 1ST ROAD, SUBHASH NAGAR, PAL ROAD JODHPUR (RAJ). SARAN CONSTRUCTION COMPANY, Prior Environment Clearance for Kadiyakhichi Crusher Stone Quarry (Temporary permit) of 1.195 Hectare Area, Khasra No. - 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 85/1, 86/2, 87 in Village – Kadiyakhichi, Tehsil – Khujner, District- Rajgarh, (M.P.) (Stone – 85,048 Cubic Meter).[460891] (MIN/460891/2024) (B2). T.P.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Mr. KRISHNA PAL SARAN, online Director, SARAN CONSTRUCTION COMPANY एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Mr. KRISHNA PAL SARAN, Director, 151, SARAN SADAN, 1ST ROAD, SUBHASH NAGAR, PAL ROAD JODHPUR (RAJ). SARAN CONSTRUCTION COMPANY, Prior Environment Clearance for Kadiyakhichi Crusher Stone Quarry (Temporary permit) of 1.195 Hectare Area, Khasra No. - 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 85/1, 86/2, 87 in Village – Kadiyakhichi, Tehsil – Khujner, District- Rajgarh, (M.P.) (Stone – 85,048 Cubic Meter). [460891] (457304).
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 85/1, 86/2, 87, एरिया— 1.195 ha., निजी भूमि
परियोजना स्थल	Village – Kadiyakhichi, Tehsil – Khujner, District- Rajgarh, (M.P.)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 1028 दिनांक 24/11/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information).
उत्पादन क्षमता	• स्टोन (गिट्टी) – 85,048 घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.195 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – सुस्तानी, जिला – राजगढ़ का उहराव प्रस्ताव क्र०. दिनांक 27/07/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - 20 Tree Felling - 02 Additional tree to be planted - 20
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा— नदी लगभग 309 मी. एवं पेट्रोल पम्प लगभग 200 मी. पश्चिम दिशा— पक्का रोड—लगभग 165 मी.
जल/वायु सम्मति वैद्यता	लागू नहीं।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 11/12/2023 अवगत कराया गया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान को अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **स्टोन (गिट्टी) – 85,048 मी³ प्रति वर्ष**।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 13.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.18 लाख प्रति वर्ष।

3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:—

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुये है अतः 25 मी. का सेड बैंक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल सुसतानी में अधोसंरचना विकास एवं 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ	1,00,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1520 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, कस्टार, सिस्सू, चिरोल, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	कड़िया खीचिं ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय	400

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

		प्रजातियाँ।	
4	02 वृक्ष माइनिंग जोन में है जिन्हे काटा जाएगा एवं इनके स्थान पर दस गुना अर्थात् 20 वृक्ष अतिरिक्त लगाए जाएंगे।		20
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. **Case No P2/308/2024 Dobi Irrigation Scheme 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. The project will provide irrigation facility in 19,468 Ha in 51 villages with both open canal and micro irrigation. [RIV/460370/2024] (TOR) Cat. 1(c) River Valley Project.**

This is a Micro Lift Irrigation Project involving >10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

PP has submitted following details on Parivesh portal.

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/RIV/460370/2024. Fresh ToR
2.	Project Name	Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, Department of Irrigation, 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, Bhopal, (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for The project will provide irrigation facility in 19,468 Ha. in 51 villages with both open canal and micro irrigation. Village – Jait, Tehsil – Budhni, Distt. – Sehore (M.P.).
3.	CCA details	CCA - 19468 Ha.
4.	Description of Project.	The project will provide irrigation facility in 19,468 Ha. in 51 villages with both open canal and micro irrigation.
5.	Reason thereof	The site has been found to be more suitable considering no forest land requirement and no submergence of any private lands or habitations and hence no R & R issues. The alignment of rising mains is selected in such a manner that its length is the shortest so that the head losses are brought to minimum. Besides this it was ensured that it does not pass through any forest land.
6.	Project Proposal For	New.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

7.	Whether the proposal involves violation	No.
8.	Dobi Irrigation Project Note (Previous EC issued by MPSEIAA details) File No. 10448/2023.	Dobi Irrigation Project EC Identification No. EC23B003MP128699 File No. 10448/2023 Category B 1(c) River Valley projects Project was granted EC on 27/10/2023 by MP SEAC as Category B2 Project as its CCA was less than 10,000 Ha. MP Government has revised the administrative approval to increase the command area of project to 19,468 Ha. Hence, the project now falls under B1 Category. Therefore, as per provisions of EIA Notification 2006 and its subsequent amendments Scoping Clearance (ToR) and Public Hearing is needed. We are applying for ToR as the project is now falling under B1 Category.
9.	Total Project Cost	24232 Lakhs.
10.	(R&R) involved	No.
11.	Any litigation pending against the project	No.
12.	CTE/CTO Status	Will be obtained after EC.
13.	DFO NOC	DFO office, Sehore Letter No. 3293 dated 24/04/2023.
14.	PWD distance letter	EE, PWD, Budhni, Distt.- Sehore Letter No. 878 dated 12/04/2023 Inter State Boundary distance -220 km (Maharashtra State).
15.	Project Approval letter dt.	31st March 2023.
16.	PFR	Submit.
17.	EMP/ Env. Con	Not disclosed.

The case was presented by the Env. Consultant Shri Ram Prasad online, and Shri Rudrksh Agarwal, Env. Co-ordinator from M/s. FECCM India Pvt. Ltd. Bhopal. along with PP Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, Department of Irrigation, 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, Bhopal, (M.P.) . PP submitted that earlier for the Dobi Irrigation Project EC vide Identification No. EC23B003MP128699 File No. 10448/2023 Category B 1(c) River Valley projects Project , was granted on 27/10/2023 by MP SEIAA under Category B2 Project as its CCA was less than 10,000 Ha.

Now, the State Government has revised the administrative approval to increase the command area of project to 19,468 Ha. Hence, the project now falls under B1 Category. Therefore, as per provisions of EIA Notification 2006 and its subsequent amendments Scoping Clearance (ToR) and Public Hearing is needed. We are applying for ToR as the project is now falling under B-1 Category.

PP submitted following information about the project :-

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

- Dobi Irrigation Scheme the project proponent NVDA targets to insure and provide irrigation facility on 19,468 Ha in 51 villages with both open canal and micro irrigation.
- The project will bridge gap between demand and supply of water requirement in the area with cannel and micro irrigation system Short supplies have been depriving farmers of bringing land under irrigation and better yield.
- The Dobi Irrigation Scheme after increasing CCA falls under Category B1|1(c) project as per EIA Notification 2006.
- Site was critically evaluated by the irrigation department and NVDA after which they finalized the location for Dobi Irrigation Scheme in Village: Dobi Jait, Tehsil: Budhni, Dist.: Sehore, MP.
- Evaluation involved analysis of topography and land elevation to use the site for advantage.
- Direct & indirect employment opportunities during construction phase will significantly contribute in uplifting quality of life of people of the region. Irrigation potential shall be created in area.

Project Details:

Project type	Linear Irrigation Scheme
CCA	19468 Ha
Villages Covered	51
District	Sehore
Project Cost	242.32 Cr
River	Narmada
Power Req.	8.43 M.W
Private Land	3 Ha
Discharge	9.58 Cumeecs

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

Environmental Sensitive area exists within 10 Km	None, NO FOREST LAND
--	----------------------

- The project is proposed on right bank of Narmada river on down stream of Jait village.
- Discharge of project: 9.58 Cumecs (99.325 MCM and 0.080 MAF).
- With 13 village with micro irrigation scheme that accounts for 5563 ha. Of CCA and 38 villages with cannel flow irrigation that accounts for 13905 ha. Of CCA that totals to 51 villages and a total of 19468 ha. Of CCA.
- 8.43 M.W. power is required for this irrigation scheme that will be provided by MPKKVCL. With 10% of renewable resources in use 0.8 KW Electricity would be used.
- Water requirement during construction stage is 200KLD and during operational stage is 355968 KLD.

The PP further submitted that project area neither involve any forest area nor submergence and R&R. The Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Status of land as per land record register of concerned Collector Office.
2. In EIA report details about existing and proposed National Parks/ WLS and their wild life management plan shall be discussed.
3. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
4. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
5. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
6. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
7. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
8. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
9. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

10. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
 11. Muck management plan w.r.t machinery deployment and movement of trucks shall be discussed in the EIA report.
 12. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
 13. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
 14. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
 15. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
 16. जल वितरण स्थानीय किसानों को किया जाना है इस के वितरण की नीति क्या रहेगी प्रस्तुत करें।
 17. जल वितरण ग्रेविटी के अनुसार किया जाना है अतः इसकी तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
 18. परियोजना की तकनीकी फिसिबिलिटी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करें।
 19. CAT Plan के अन्तर्गत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य को नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
 20. CAT Plan के अन्तर्गत फलदार पौधों का वितरण प्रस्तुत करें।
 21. CAT Plan के अन्तर्गत यदि भूस्वामी की सहमति हो तो तालाब निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
 22. प्रस्तावित पौधा रोपण जानकारी नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
 23. Separate CAT plan as per legal status of land and approved by competent authority.
 24. Biodiversity and Wildlife Conservation plan में गतिविधियाँ दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
 25. Carbon footprint के अन्तर्गत पेड़ काटने के फलस्वरूप कितना कार्बन फुटप्रिन्ट निर्मित होगा कि जानकारी प्रस्तुत करें।
 26. भारत सरकार की कॉस्ट बैनिफिट पॉलिसी प्रस्तुत करें।
 27. **Top soil management Plan.**
 28. Submit proper CER with appropriate budget of CER of 2%.
 29. Muck management plan with financial implication in the EMP.
18. **Case No 9876/2023 Chief Engineer, NVDA Lower Narmada Projects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar Indore (MP) Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75,000 Ha. of CCA in Dhar district. (115 villages of Kukshi Tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 01 village of Dahi Tehsil and 33 villages of Manawar Tehsil, District-Dhar) (MP). Amendment in TOR.**

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

This is a Micro Lift Irrigation Project involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

Earlier, in the SEAC 646th Meeting dated 16th May 2023 ToR was recommended by the SEAC for the proposed project.

Then , PP has applied for Amendment in ToR for which PP has applied requisite form -3 . Hence, this case was scheduled in the 672nd meeting on dated 25.08.2023.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri R. S. Mandloi, Executive Engineer, NVDA, Dhar. During presentation PP was submitted that after conducting detailed survey and investigation, total land requirement for the proposed project has changed from 40.15 ha. to 251.69 ha. PP further stated that forest area has also increased earlier it was involved 33.90 ha. now increased upto approx. 220 ha. for which F.C. clearance shall also obtained.

The Committee observed that during presentation PP / Env. Consultant was not able to shown forest area on the Google earth /map hence; committee was not able to reach any conclusion in this regard. After deliberation the committee asked PP to submit revised map showing complete revised project area passing including forest area . The committee also asked PP to aware them regarding status of EC compliance of last 2 years with credible evidence.

The project proponent submitted clarification on 13.09.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 672nd meeting on dated 25.08.2023. Hence, the case was scheduled in the agenda of SEAC 682nd meeting 26/09/2023.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri R. S. Mandloi, Executive Engineer, NVDA, Dhar with the following details of the project:

Chronology of the project :

Actions	Date
Filing of TOR Application	21.04.2023
SEAC Meeting for TOR Clearance	16.05.2023

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

SEIAA Meeting for TOR Clearance	31.05.2023
TOR approved and received from SEIAA	06.06.2023
Revised Form 1 and letter submitted for amending the TOR	14.08.2023
SEAC Meeting for TOR Amendment	25.08.2023
ADS reply uploaded	13.09.2023

Reasons for Amendment of TOR

PP submitted that after conducting detailed survey and investigation, total land requirement for the proposed project increased from 40.15 ha to 251.69 ha. All the other project features will remain unchanged.

The bifurcation of land (forest & non- forest) are as given blow:-

Land Requirement Comparison		
	As per Tor Granted	Present
Forest (ha)	33.9	220.44
Non-Forest (ha)	6.25	31.25
Total	40.15	251.69

Committee accepted the request made by PP and recommended to amended in TOR with the inclusion of following amendments in the configuration of the project:

- Updated the Non-Forest Land from 6.25 ha to 31.25 ha and Forest Land from 33.9 ha to 220.44 ha.
- As forest land is involved in the project FC stage-I to be clarified with supporting documents along with catchment area improvement and natural drainage protection plan shall be discussed in the EIA report.
- CAT improvement plan shall be carried out through forest department.
- Under CER activity proposal for Bagh River re-juvenation.
- In EIA report details about existing flora & fauna and their Ecological damage plan shall be discussed.
- Soil & water conservation plan shall be prepared through forest department.
- Impacts on forest due to pipelines laying in this context opinion to be taken from concerned DFO.

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

- PP shall be submitted the EC compliance report w.r.t plantation and CER activities of similar projects, along with EIA report.
- PP shall produce the compliance report of old sanctioned project of EC specially regarding plantation works & CER activities which were imposed in old cases , where EC had been issues.

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in 646th Meeting dated 16th May 2023.

PP has further applied for Amendment in ToR. Hence, this case was scheduled in this meeting.

In the SEAC 732th meeting dated 20/03/2024 the case was presented by the Mr. Vial Gag, Envy. Consultant from M/s. R. S. Environing Technologies Pvt. Ltd, Gorgon (Haryana) along with PP Shri G.P. Upadhyay , Executive Engineer, NVDA, Dhar .

PP submitted following details of the project:

Actions	Date
Filing of TOR Application	21.04.2023
TOR approved and Letter Issued by SEIAA ()	06.06.2023
TOR was amended for change in Land Requirement; TOR Amendment was issued by SEIAA	26.10.2023
No. of benefitted villages got revised from 175 to 247 without changing the command, however, this did not get mention in previous amendment application; therefore TOR amendment is requested again to put the factual data on documents. Revised Form 1 and letter submitted for further TOR amendment to put it on record.	09.02.2024

PP submitted chronology of the project along with reasons for Amendment in the proposed TOR-

- Scoping clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Scheme was accorded by SEIAA vide their letter No. 640/SEIAA/2023 dated 06/06/2023.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

- Amendment in ToR for Kukshi Micro Lift Irrigation Scheme due to change in land requirement; accorded by SEIAA vide their letter No. 1837/SEIAA/2023 dated 26/10/2023
- **List of benefitted villages, got revised to 247 villages instead of 175 villages, however, this did not get mention in previous TOR application.**
- **All the parameters of the scheme including land requirement (251.69 ha) and CCA will remain the same i.e. 75000 ha.**

Comparative Statement for the changes

S.No.		ToR including amendment	Revised for which TOR amendment is requested
1.	Gross Command Area	137064	140972
2.	Tehsils	Kukshi & Gandhwani	Kukshi, Gandhwani, Dahi & Manawar
3.	No. of Villages	175	247
		96 villages of Kukshi tehsil & 79 villages of Gandwani tehsil	115 villages of Kukshi tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 1 village of Dahi tehsil and 33 villages of Manawar tehsil

Justification

- During detailed survey and investigation, it is observed that significant portions of these villages are not suitable for cultivation, either due to being barren, undulated or situated on hilly terrain.
- Therefore, to compensate for the reduction in CCA for which the project is designed, the land adjacent to these villages where cultivation is going and there is need for irrigation water supply have been identified.
- Change in number of benefitted villages and tehsil did not get mention in the previous TOR application.
- All the parameters of the scheme including land requirement and CCA is same.

Project Description

- 29.25 cumec water will be lifted directly from river Narmada at elevation 112.00 m to 560.00 m to cater to irrigation demand of about 75,000 ha CCA in Dhar district.
- Total 115 villages of Kukshi tehsil, 98 villages of Gandhwani tehsil, 1 village of Dahi tehsil and 33 villages of Manawar tehsil of Dhar district will be benefitted.
- Apart from irrigating 75,000 ha of land, 1.5 cumec of water exclusively earmarked for drinking purposes and 1.5 cumec for filling the existing dams/canal systems.
- The scheme contains an approach channel, 6 Nos. Pump Houses and 7 Nos. Distribution Chambers at different suitable locations along the rising mains, gravity mains and distribution network.
- A pipe network of approx. 8600 KM will be laid to serve 75000 ha of land at different levels.

PP further submitted before the committee that:

- There is no change in other project features.
- ToR amendment is being requested to update the GCA from 137064 ha to 140972 ha and No. of villages from 175 to 247.
- We request the committee to approve the amendment of TOR, so that EC process can be completed and the work will be initiated.

Committee accepted the request made by PP and recommended to amended in TOR with the inclusion of following amendments in the configuration of the project:

Update the GCA from 137064 ha to 140972 ha and No. of villages from 175 to 247.

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in 646th Meeting dated 16th May 2023& SEAC 682nd meeting 26/09/2023.

19. **Case No P2/311/2024 Bijawali Stone Quarry (Temporary Permit) Pemanent Address SCO-5, Second Floor, Huda Market,Near Hero Honda Chowk, Sector10A,District-Gurugram. It is a Temporary Permit Stone Quarry with a production capacity of**

**732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024**

2,00,000 m³/year Stone/Boulder having a lease area of 2.40 hectare, at Khasra No. 406/1 (Govt. land) Village - Bijawali, Tehsil- Buxwaha, District Chhatarpur (M.P.). [MIN/462332/2024] (B2) . T.P.

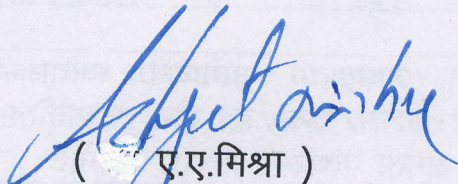
प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sohan Lal Saini, on-line एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।


परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Shri Sohan Lal Saini, Authorized Signatory, M/s JEET ASIA PRIVATE LIMITED, Current Add:- Chicholi, Tehsil -Chicholi , District Betul(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	406/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.40 hectare.
स्थल	Village - Bijawali, Tehsil- Buxwaha, District- Chhatarpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 3193 दिनांक 28/12/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-2,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-2,00,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 206 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 206 दिनांक 08/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 206 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 मार्च 2024

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मड़िया बुजुर्ग जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 16/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- स्टाप डेम लगभग 40 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 214 दिनांक 09/01/24 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि निर्धारित सेटबैक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 19/03/24 अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लारिस्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।


(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव


(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yeears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

732वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2024

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम उतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे